साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 09 अगस्त 2021, वर्ष-7, अंक-19

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

तबाही की मूसलाधार

23 हजार से ज्यादा मकान टूटे

25 हजार हेक्टेयर की फसल बर्बाद

» कैबिनेट में बाढ़ की स्थिति को लेकर दिया गया प्रस्तुतीकरण

» नगरीय क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया, हैंडपंप, पाइप लाइन को पहुंचा नुकसान

» अभी 15 गांव पानी से घिरे हैं, जबकि 276 गांव में पानी उतरा

» बाढ़ प्रभावित जिलों में बांधों का जल स्तर फिलहाल स्थिर हुआ

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से अधोसंरचना और कृषि क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका वास्तविक आकलन तो बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद होगा पर जो प्रारंभिक आकलन हुआ है, उसके मुताबिक 23 हजार से ज्यादा मकान टूटे हैं। 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। नगरीय क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया, हैंडपंप और पाइप लाइन को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की स्थिति को लेकर कैबिनेट में गृह विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल सहित अधोसंरचना को पहुंचे नुकसान का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वाधिक 706 पशुओं की मौत शिवपुरी हुई है। यहां 23 हजार से ज्यादा मकान टूट गए हैं। इनमें 15 हजार से ज्यादा अकेले श्योपुर में हैं। इसकी संख्या और बढ़ेगी। शिवपुरी में 18 हजार हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। इस पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि नुकसान ज्यादा हुआ है। वहीं, मुरैना, श्योपुर और गुना में फसलों को क्षति का प्रारंभिक अनुमान अभी नहीं आया है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

सब बर्बादः बाढ़ की वजह से बिजली से जुड़ी अधोसंरचना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। साढ़े पांच हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन और बिजली के खंबे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जल संसाधन विभाग की 315 लघु, मध्यम और वृहद संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। नगरीय क्षेत्रों में ढाई हजार हैंडपंप, पाइप लाइन, सड़कें और पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 सड़क, पुल और पुलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पांच सौ से ज्यादा आंगनबाड़ी और पहुंच मार्ग को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि हालात सामान्य होने पर कुल नुकसान का आंकड़ा सामने आएगा।

केंद्रीय टीम भेजें: राज्य शासन ने बाढ़ से हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार से तुरंत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग कुल नुकसान का आंकलन करने के लिए मैदानी सर्वे कर आंकड़े भी जुटा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि केंद्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के मूल्यांकन से प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत जल्दी से जल्दी अतिरिक्त सहायता दी जाए।

सीएम शिवराज बोले

मैंने जिंदगी में नहीं देखी ऐसी आपदा

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। जैसे-जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी, उसके साथ ही हमें क्षति के आकलन के लिए सर्वे प्रारंभ करना है, ताकि नुकसान की भरपाई शीघ्र की जा सके। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज प्रदान करेंगे। शिवराज ने इसे भीषण प्राकृतिक आपदा करार देते हुए कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आपदा नहीं देखी। जब मैं कल गांव-गांव गया, लोगों के बीच, तो पाया कि मकान मात्र मलबों का ढेर रह गए। हजारों मकान ढेर हो गए। घरों में रखा सामान नष्ट हो गया। अनाज अंकुरित हो गया, बर्तन, कपड़े, जरूरत की सारी चीजें चली गईं। मवेशी बह गए और कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ बचा नहीं है। बिजली के सब स्टेशन, बिजली के खंभे, टेलीकम्युनिकेश की सब व्यवस्था, सड़कें, पुल... भयानक तबाही है। बाढ़ प्रभावित लोग चिंता न करें। सरकार जनता राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

अन्न उत्सवः प्रधानमंत्री मोदी बोले- पहले आती थीं घोटालों की खबरें अब मप्र गढ़ रहा नए-नए कीर्तिमान

मप्र के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को मिला मुफ्त राशन

संवाददाता, भोपाल

मप्र में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हितग्राहियों से बात की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बुरहानुपर के राजेंद्र शर्मा से बात की, इसके बाद होशंगाबाद की माया उइके, सतना के दीप कुमार कोरी और निवाड़ी के चंद्रभान विश्वकर्म से बात की। मोदी ने कहा कि हम कारोना के शुरू होने के दौरान 80 करोड़ गरीबों के घर राशन पहुंचा रहे हैं। कभी गरीबों के घर जाकर बात करने का मौका नहीं मिला, आज मैं गरीब भाई-बहनों का दर्शन कर रहा हूं। इससे गरीबों के लिए कुछ करने की ताकत मिलती है। सरकार से मुफ्त अनाज से बड़ी राहत मिली। पहले मध्यप्रदेश में बड़े-बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज यहां के शहर नए-नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं।

-संबंधित पेज 8 पर

4.90 करोड़ लोगों को राशन

मध्य प्रदेश के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिला। कुल 1 करोड़ 15 लाख परिवार लाभांवित हुए। प्रदेश की 25 हजार 435 दुकानों पर लाभार्थियों को राशन मिला। सभी 52 जिलों में मंत्री, सांसद एवं विधानसभा मौजूद रहकर राशन वितिरत किए। इसके अलावा चार राज्यों के खाद्य मंत्री भी आयोजनों में शामिल हुए।

बाढ़ जिलों में 60 किलो राशन

मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिले शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन राशन का वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावितों को 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया गया। यानी उन्हें कुल 60 किलो राशन मिला।

इनका कहना है

एक करोड़ 15 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन राशन दिया जाता है। 37 लाख लोगों की पर्ची नहीं बनी थी, उन्हें भी योजना में जोड़ा। उन्हें भी राशन वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में राशन वितरण किया गया। ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ के कारण आवागमन बंद है। बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बाद बाढ़ प्रभावितों को 50 किलो अनाज देंगे।

बिसाहूलाल सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री

खाद्य की सेवा के लिए सहकारिता विभाग हमेशा तैयार है। देश के सात राज्यों से नेता और अधिकारी मध्य प्रदेश में आए हैं। बाढ़ प्रभावित सात जिलों (भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना) में कार्यक्रम नहीं हुए। सभी जिलों में कार्यक्रम का मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्रियों के अलावा जनप्रतिनिधियों को बनाया गया था।

अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री

15 गांवों के 300 लोगों को मिलेगा रोजगार

देशभर में बेचा जाएगा अब बालाघाट का शहद

भोपाल। बालाघाट का शुद्ध शहद अब पूरे देश में जल्द ही बिक सकेगा। जिले में पहली व्यावसायिक उत्पादन यूनिट वन परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य चरेगांव में प्रारंभ की गई है। यूनिट का संचालन 15 ग्रामों में 15 स्व सहायता समूह के 300 सदस्य करेंगे। शहद के शुद्धीकरण से लेकर बेचने का काम समूह के सदस्य ही करेंगे। मुनाफा भी समूह को मिलेगा। दरअसल, आदिवासी हर साल नवंबर से जून तक यानी आठ माह तक जंगलों से शहद निकालते हैं और बिचौलियों को 100-150 रुपए किलो बेच देते हैं। अब वन विभाग ने प्रधानमंत्री वन धन शहद प्रसंस्करण केंद्र शुरू किया है। वन विभाग खरीदेगा 200 से 300 रुपए किलो। फिर मशीन के जरिये शुद्ध करके शहद की 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम सहित अन्य बोतलों में भरा जाएगा। बालाघाट वन विभाग के नाम से स्टीकर चिपकाकर ऑनलाइन व ऑफ लाइन दोनों तरीके से बेचा जाएगा।

शुद्ध करेंगे

भोपाल से करीब छह लाख रुपए में शुद्धीकरण मशीन भी मंगवाई गई है। यूनिट में पूरे रेंजों का शहद खरीदकर शुद्धीकरण किया जाएगा।

आदिवासियों को रोजगार दिलाने के लिए शहद शुद्धीकरण प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। बालाघाट वन विभाग के नाम से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बेची जाएगी।

-एनके सनोड़िया, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट

- गोबर धन योजना में लगेगा बॉयोगैस संयंत्र
- 2022 तक 9500 संयंत्र लगाने का लक्ष्य
- पारंपरिक ईंधनों पर कम होगी निर्भरता
- रसोई को स्वच्छ व धुआं रहित बनाएंगे

प्रदेश की ढाई हजार स्कूलों में बॉयागैस से पकेगा मध्याह्न भोजन

संवाददाता, भोपाल

खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ऐसे 2549 स्कूलों में बॉयोगैस संयंत्र लगाने जा रही है, जिनमें रोज दो सौ से अधिक विद्यार्थियों का मध्याह्न भोजन तैयार होता है। यह व्यवस्था गोबर धन योजना के तहत की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में 9500 बॉयोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया है। जरूरत और मांग के अनुसार सामुदायिक, सामूहिक व व्यक्तिगत संयंत्र भी लगाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (द्वितीय चरण) के तहत खाना पकाने के लिए रसोई को भी स्वच्छ एवं धुआं रहित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बॉयो एग्रो रिसोर्सेस (गोबर धन) परियोजना लाई गई है। इसी के तहत बॉयोगैस संयंत्र निर्माण हो रहे हैं।

सामूहिक संयंत्र होंगे

कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, इसलिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला और पांच से 10 घरों के बीच 20 से 25 सामूहिक बॉयोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी एजेंसी के रूप में ऊर्जा विकास निगम एवं एमपी एग्रो से सहयोग लिया जा रहा है।

पंचायत देगी प्रस्ताव

बॉयोगैस संयंत्र के लिए ग्राम पंचायत स्थल चयन कर अनुशंसा सहित प्रस्ताव जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी। जनपद से प्रस्ताव जिला पंचायत में पहुंचेंगे। जहां जिला स्तरीय तकनीकी समिति परीक्षण कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगी।

खेती होगी आसान! हर्बिसाइड से सिंचाई तक की मिलेगी जानकारी

- खरपतवार से निपटने में मदद करेगा हर्बीसाइड कैलकुलेटर ऐप
- देशभर के किसानों को अब और परेशान नहीं होना पड़ेगा

खास बातें

- रबी, खरीफ और जायद की तमाम फसलों को इसमें जोड़ा गया है।
- कौन सा हर्बिसाइड उपयोग करना चाहते हैं, इसका भी ऑप्शन है।
- जमीन के हिसाब से कितना हर्बिसाइड उपयोग करें, बताएगा ऐप।
- खरपतवार के प्रबंधन के लिए कितना डोज उपयुक्त मिलेगी जानकारी।
- भूमि के हिसाब से सिंचाई के बारे में भी बकायदा जानकारी दी गई है।

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

भारत में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किसान खेती से किनारा कर रहे हैं। इसके पीछे किसानी में ज्यादा लागत और कम मुनाफा एक वजह बताई जाती रही है। भारत सरकार की तरफ से किसानों को इस स्थिति में जाने से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं और ऐप लॉन्च किए जाते रहे हैं। HERBCALनाम से ऐसा ही ऐप ICAR-DWR (खरपतवार अनुसंधान निदेशालय), जबलपुर ने लॉन्च किया है। इसमें किसानों को एक खेत में खरपतवार प्रबंधन के लिए कितना हर्बिसाइड डालना है इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

जागरुकता की कमी से नुकसान

किसान अक्सर जागरुकता की कमी की वजह से फसलों की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इससे फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न कृषि संस्थाओं की तरफ से खेती किसानी से जुड़े तमाम ऐप लॉन्च किए गए हैं। जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके।

कैसे करें ऐप डाउनलोड

इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। वहां से आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पहले पेज पर ही क्रॉप सेलेक्शन का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। जहां पर रबी, खरीफऔर जायद की फसलों को आप चुन सकते हैं और उनकी किस तरह से देखभाल करना है जान सकते हैं। इस ऐप को एक तरह से हर्बिसाइड कैलकुलेटर की संज्ञा दी गई है।

वैज्ञानिकों के नंबर भी उपलब्ध

किसान अगर इससे अतिरिक्त भी कोई जानकारी चाहते हैं या ऐप से मिली जानकारी के बाद भी उनकी समस्याएं भी दूर नहीं होती हैं। तो इस ऐप में संस्थान के डायरेक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक का मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी दिया गया है। किसान उनसे सीधे संपर्क कर अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं।

खरपतवार की पहचान करेगा वीड मैनेजर

निदेशालय ने एक और ऐप वीड मैनेजर भी विकसित किया है, जिसमें हर तरह के खरपतवार की जानकारी है। वीड मैनेजर की मदद से किसान हर एक खरपतवार की पहचान सकता है। साथ ही रसायनिक और यांत्रिक विधियों से इनके नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों के साथ ही स्टूडेंट्स, एनजीओ, वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी भी इससे जानकारी ले सकते हैं।

इनका कहना है

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय ने इस हर्बीसाइड कैलकुलेटर ऐप को विकसित किया है। यहां पर वैज्ञानिक किसानों को खरपतवार प्रबंधन की जानकारी देते हैं, पूरे देश में निदेशालय के 23 केंद्र हैं। किसान इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि किसानों का सवाल होता है कि उन्हें रबी की फसल की जानकारी चाहिए। जब किसान उस पर जाएगा और रबी पर क्लिक करेगा तो देश भर में रबी की जितनी फसलें होती हैं सब आ जाएंगी।

डॉ. पीके सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय

-2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से दिया जाए कृषि भूमि का मुआवजा

लैंड पूलिंग एक्ट से आईडीए को जमीन देने से किसानों का इनकार

इंदौर। किसानों ने लैंड पूलिंग एक्ट के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) को अपनी कृषि भूमि देने से इनकार किया है। किसानों का कहना है कि आईडीए ने राज्य शासन को पांच योजनाएं मंजूरी के लिए भेजी थीं, लेकिन शासन ने किसानों और भूमि स्वामियों को भरोसे में लिए बगैर इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस मामले में किसान शोषण विरोधी मंच और किसान सेना के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। मंच के अध्यक्ष दिलीप सिंह पंवार और किसान सेना के अध्यक्ष केदार पटेल ने बताया कि यदि शासन किसानों की जमीन लेना ही चाहता है तो केंद्र सरकार के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा प्रदान करे। वर्ष 2013 के भू-अर्जन कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय गाइडलाइन से 4 गुना और शहरी क्षेत्र में दुगुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ लैंड पूलिंग एक्ट के तहत किसानों की 50 प्रतिशत भूमि बिना कीमत चुकाए ली जा रही है। बची हुई 50 प्रतिशत जमीन में सिर्फ सड़क बनाकर देने का प्रविधान है। इससे किसानों को नगर तथा ग्राम निवेश से दोबारा अनुमति लेना पड़ेगी। किसानों को अपनी बची हुई जमीन भी विकसित करना पड़ेगी। ऐसे में किसानों ने निर्णय लिया है कि लैंड पूलिंग एक्ट के तहत किसी भी हाल में अपनी कृषि भूमि नहीं देंगे।

सस्ते में नहीं देंगे: इंदौर की कृषि भूमि सिंचित, उपजाऊ और बहुफसलीय है। इतनी कीमती जमीन लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते में नहीं दी जा सकती। किसान की जमीन छिन जाने के बाद उसके पास गुजर-बसर के लिए कोई साधन नहीं होगा। यदि पर्याप्त मुआवजा मिलता है तो वह इससे कहीं और जमीन खरीदकर खेती कर सकेगा या अन्य कोई रोजगार शुरू कर सकता है।

किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में लगेगी अत्याधुनिक मानक परीक्षण मशीन!

» मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पहलः प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने देखा डेमो

» किसानों को मिलेगी उपज की गुणवत्ता रिपोर्ट और सुरक्षित रहेगा पूरा रिकॉर्ड

» हरियाणा-राजस्थान के बाद मध्यप्रदेश की मंडियों में मशीन लगाने की तैयारी

» एक मशीन की कीमत 14 लाख, ट्रायल में सफलता के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के किसानों की उपज की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण मशीन लगाई जाएगी। प्रयोग के तौर पर अभी कुछ चुनिंदा मंडियों में यह मशीन लगाई जाएगी। आशा अनुरूप परिणाम आने के बाद सभी मंडियों में लगाई जाएगी। मंडियों में आधुनिक मशीन लगाने की पहल मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा की जा रही है। इस मशीन की खास बात यह है कि मंडी में लगने के बाद फसल की गुणवत्ता को लेकर हो रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने हाल ही में स्थानीय कृषि उपज मंडी भोपाल (करोंद) में आर्टिफिशियल एन्टलीजेंस साफ्टवेयर आधारित एक अत्याधुनिक असेइंग मशीन का अवलोकन किया और डेमो भी देखा। इस मशीन की विशेषता यह है कि इसमें कृषि उपज की दोनों साइड से फोटो लेकर जिन्स की गुणवत्ता की जांच होती है। जिसमें जिन्सों के टूटे हुए, सड़े हुए, सिकुड़े हुए, अन्य जिन्स के दानों, कचरा, डंठल, मिट्टी, पत्थर आदि की अलग-अलग फोटो अपलोड होकर इनकी मात्रा के प्रतिशत अनुसार असेइंग रिपोर्ट प्रदर्शित होती है। इस असेइंग (गुणवत्ता) रिपोर्ट को प्रत्येक किसान के नाम अथवा लाट नंबर से मशीन में सुरक्षित रखकर आवश्यकता अनुसार किसान को असेइंग रिपोर्ट का प्रिंट भी दिया जा सकता है। असेइंग मशीन का डेमो देखने के बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों की सुविधा के लिए उक्त मशीन को भविष्य के लिए कारगर बताया।

अब किसान नहीं होंगे परेशान

मप्र राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की आयुक्त सह प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने करोंद स्थित पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्य रूप से प्रबंध संचालक ने मंडी प्रांगण का भ्रमण कर मंडी समिति भोपाल द्वारा बनवाए जा रहे जी +3 कमर्शियल काम्पलेस का निरीक्षण किया। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल मंडी द्वारा सात कमर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में 01 जी +3 कमर्शियल काम्पलेस का निर्माण निशातपुरा रेलवे फाटक की तरफ किया जा रहा है। जिसमें 638 मीटर की 11 दुकाने, 334 मीटर की 22 दुकानें, 639 मीटर की 11 दुकानें बनवाई जा रही है।

समय पर पूरा हो निर्माण

निरीक्षण के दौरान प्रबंध संचालक ने उपस्थित तकनीकी अमले को कार्य समय पर पूरा करने, गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सभी मानकों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही आने वाले समय में मंडी प्रांगण को सुव्यवस्थित रूप से कमर्शियल काम्पलेक्सों का निर्माण चरणबद्ध तरिके से करने के निर्देश दिए गए।

इनका कहना है

कृषि उपज मंडी करोंद में आधुनिक मानक परीक्षण मशीन का डेमो देखा है। अभी प्रदेश की एक या दो मंडियों में इस मशीन को प्रायोगिक रूप से चलाकर इसका परीक्षण किया जाएगा। आशानुरूप सफल परिणाम आने पर इसे मप्र की अन्य मंडियों में विशेष कर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की मंडियों में लगवाने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रियंका दास, प्रबंध संचालक, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मंडियों में आधुनिक मानक परिक्षण मशीन लगाने की हमारी तैयारी है। लेकिन अभी हम मशीन का प्रयोगिक तौर पर डेमो देख रहे हैं। कंपनी अभी हरियाणा और राजस्थान में इस तरह की मशीन लगाने की बात कही है। एक मशीन की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। सफल परीक्षण पर शासन से अनुमति के बाद मंडियों में यह मशीन लगाई जाएगी।

संगीता ढोके, संयुक्त संचालक, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

हड़ताल की निकली हवा! एफआईआर, निलंबन और बर्खास्ती के डर से काम पर लौटे पंचायतकर्मी

» अन्न उत्सव में 70 हजार कर्मचारी हुए शामिल, प्रांताध्यक्ष बोले-कार्रवाई वापस लेगी सरकार

» पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया से मिलने और आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में बीते 15 दिन से आंदोलन कर रहे पंचायतकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। करीब 70 हजार कर्मचारी अब पंचायतों में काम पर लौट आएं हैं। साथ ही शनिवार को अन्न उत्सव में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के प्रांताध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि हड़ताल अवधि के दौरान प्रदेश में 1500 से अधिक कर्मचारियों पर एफआईआर, निलंबन एवं बर्खास्ती की कार्रवाई हुई थी। सरकार ने यह कार्रवाई वापस लेने का भरोसा दिलाया है। साथ ही मांगों के निराकरण करने की भी बात कही है। इसलिए हड़ताल समाप्त कर दी है। इस मसले पर 20 अगस्त को मीटिंग भी की जाएगी। दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया से संयुक्त मोर्चे के विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी। इसके बाद वे बिना शर्त के हड़ताल समाप्त करने पर राजी हो गए। हालांकि, मंत्री ने संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों को उनकी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराने का आश्वासन दिया है।

प्रांताध्यक्ष जिलाबदर

पंचायतकर्मी भोपाल समेत प्रदेश के कई स्थानों पर अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा मुंडन एवं मटके फोड़कर भी विरोध जता रहे थे। इस पर कैबिनेट की बैठक में सीएम ने नाराजगी जताई थी और अनुशात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद रतलाम, नीमच समेत कई जिलों में पंचायतकर्मियों पर एफआईआर, निलंबन व बर्खास्ती की कार्रवाई की जाने लगी। चार-पांच दिन में ही डेढ़ हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। प्रांताध्यक्ष शर्मा को भी मंदसौर कलेक्टर ने जिलाबदर भी कर दिया था। समझा जा रहा है कि कार्रवाई के चलते कर्मचारी झूके और हड़ताल वापस ले ली।

मनरेगा के काम ठप

मप्र में प्रवासी मजदूरों और गांव में काम करने वाले श्रमिकों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी। हड़ताल के कारण जिन 11 लाख से अधिक मजदूरों को रोज काम मिलता था, यह संख्या घटकर 32 हजार रह गई थी। कुल 1 करोड़ 20 लाख मजदूरों की तुलना में यह 0.27 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति मप्र के इतिहास में पहली बार बनी है, जब मनरेगा के काम हड़ताल के कारण ठप हो गए थे।

प्रदेशभर के कालेज-विवि ने दो हजार गांवों के विकास की उठाई जिम्मेदारी

इंदौर। गांव का विकास करने को लेकर शैक्षणिक संस्थानों ने इन्हें गोद लिया है। बीते दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने संस्थानों से गांवों के बारे में जानकारी बुलवाई थी, जिसमें यह सामने आया है कि प्रदेशभर के कालेज-विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों ने करीब दो हजार गांव की दिशा बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। मामले में संस्थानों से विकास से जुड़ी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अगले महीने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव इनकी समीक्षा करेंगे। यहां तक संस्थानों को विकास व सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा। पंद्रह दिन पहले विभाग ने संस्थानों से गोद लिए गांवों और विकास के बारे में पूछा था। लगभग अधिकांश कालेज व विश्वविद्यालय ने आवेदन भेजे। 62 प्रतिशत संस्थानों ने दस किमी दायरे में आने वाले गांवों में विकास करना बताया, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, सड़क-टायलेट निर्माण, सरकारी योजना का प्रचार-प्रसार की गतिविधियां बताई। यहां तक कुछ कालेजों ने पहली मर्तबा गांव गोद लेना बताया है। आवेदनों के हिसाब से करीब दो हजार गांवों हो चुके हैं। संस्थानों को सालभर किए जाने वाले कार्य बताना है। ताकि इन गांवों की स्थिति में बदलाव आ सके। विभाग ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें अगले महीने कार्यों की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके आधार पर संस्थानों को गांव में विकास कार्य करना है। यहां तक प्रत्येक छह महीने में रिपोर्ट भी देना होगी। सरकारी, निजी और अनुदान कालेज के अलावा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय शामिल है।

सितंबर में उच्च शिक्षा मंत्री यादव करेंगे समीक्षा, कार्ययोजना का प्रस्ताव मांगा

भदावरी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

दुनिया में सर्वाधिक वसा प्रतिशत के लिए पहचानी जाने वाली भैंस की भदावरी नस्ल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष की प्रमुख नस्ल है। इसकी उत्पति एवं उद्भव इस क्षेत्र को माना जाता है। यह नस्ल इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थितियों एवं जलवायु के अनुकूल है। आजादी से पूर्व आगरा, इटावा, भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर जनपदों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक छोटा सा राज्य था जिसे भदावर एस्टेट के रूप में जाना जाता था। भैंस की यह नस्ल भदावर राज्य में ही विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम भदावरी पड़ा। वर्तमान में इस नस्ल की भैंस आगरा की बाह तहसील, भिंड के भिंड और अटेर तहसील, इटावा (चकनगर, वढ़पुरा) औरैया तथा जालौन में यमुना किनारे और मुरैना में चंबल नदी के आस-पास एवं ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों में देखी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत के अनुसार विगत कई सालों से भदावरी नस्ल की भैंसों की संख्या लगातार

घटती जा रही है। इसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में भदावरी नस्लों के पड़ों का अभाव और किसानों का मुर्रा नस्ल की तरफ बढ़ता रुझान है। वर्तमान में भदावरी नस्ल की भैंस अपने पंरपरागत क्षेत्रों में भी कम ही दिखाई देती है। यह कहना गलत नहीं होगा यदि यही हाल रहा तो यह नस्ल कुछ ही वर्षों में अपने पैत्रिक क्षेत्र से ही विलुप्त न हो जाए। भदावरी नस्ल के पशुओं का शारीरिक आकार मध्यम, रंग तांबिया तथा शरीर पर बाल कम होते हैं। टांगे छोटी व मजबूत होती हैं। घुटने के नीचे का हिस्सा हल्के-पीले रंग का होता है। सिर के अगले हिस्से पर आंखों के ऊपर वाली भाग सफेदी लिए हुए होता है। गर्दन के नीचे भाग पर दो सफेद धारियां होती हैं जिन्हे कंठमाला अथवा जनेऊ कहते हैं। अयन अथवा इसके आसपास की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। सींग नुकीले तलवार के समान होते हैं। इस नस्ल के पशुओं का औसत वजन 300 से 400 किलो तक होता है। छोटे आकार एवं कम वजन होने के कारण इसे कम संसाधनों के साथ लघु सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों द्वारा बखूबी पाला जा सकता है। इस नस्ल के पशु विषम परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखते हैं। अति गर्म और आर्द्र जलवायु में भी आराम से रह सकते हैं। इस नस्ल के नर उच्च तापमान को सहन करने के साथ ही अच्छे भारोत्तोलक होते हैं। इस नस्ल के पशु कई बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधी पाए गए हैं। भदावरी भैंस के बच्चों में भी मृत्युदर भैंसो की अन्य नस्लों की तुलना में काफी कम है। भदावरी भैंस की नस्लों से औसतन एक ब्यांत में 1200 से 1400 किग्रा तक दूध प्राप्त होता है। भदावरी भैस प्रतिदिन औसतन 4 से 5 किलो तक दूध दे देती है। भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वसा का प्रतिशत पाया जाता है। इस भैंस के दूध से सर्वाधिक 8.5 से लेकर 14 प्रतिशत तक वसा की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यह नस्ल मोटा चारा-दाना खाकर उसको अच्छी वसा प्रतिशत में बदलने की क्षमता रखती है। गांवों में एक कहावत है कि भदावरी भैंस के आठ दिन के दूध में एक दिन के दूध की मात्रा के बराबर घी निकलता है। अर्थात प्रतिदिन 5 किलो दूध देने वाली भैंस से आठ दिन में 5 किग्रा घी निकल आता (12.5 प्रतिशत के बराबर) है। दूरदराज के गांवों में जहां दूध बिक्री कर पाना मुश्किल होता है। वहीं पशुपालकों को दूध की कीमत भी बहुत कम मिल पाती है। इन दूरदराज के गांवों के पशुपालक किसान कम खर्चे एवं कम देखभाल में भदावरी नस्ल का पालन करके दूध से अधिक मात्रा में घी बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस नस्ल के संरक्षण का कार्य भदावरी भैस संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना के तहत भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी पर नेटवर्क परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भदावरी नस्ल के संरक्षण एवं सुधार के लिए उत्तम सांड़ों (पड़ों) का विकास किया जा रहा है। परियोजना में भदावरी पड़ों का वीर्य हिमीकरण करके उसको भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित ही नहीं रखा जा रहा है, अपितु इस नस्ल के प्रजनन क्षेत्र आगरा, इटावा, मुरैना, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी आदि जिलों में भी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा परियोजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रजनन के लिए उच्च कोटि के सांड तथा उनका वीर्य किसान-पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराना है। भदावरी नस्ल के पशुओं के संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए झांसी से मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कट विकास परिषद, भोपाल, पशुधन विकास परिषद, लखनऊ, बैफ, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान (दुवासु) मथुरा आदि स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जिनका उपयोग प्रजनन एवं वीर्य हिमीकरण के लिए किया जा रहा है। आज भदावरी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इनका का संरक्षण एवं संवर्धन करने की जरूरत है जिससे उनके उत्पादन एवं वर्तमान स्थिति में सुधार किया जा सके। बदलती हुई जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों की चुनौतियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भदावरी जैसी भैंस की नस्ल भविष्य का दुधारू पशु है।

> दुनिया में सर्वाधिक वसा प्रतिशत के लिए पहचानी जाने वाली भैंस की भदावरी नस्ल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष की प्रमुख नस्ल है। इसकी उत्पति एवं उद्भव इस क्षेत्र को माना जाता है। यह नस्ल इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थितियों एवं जलवायु के अनुकूल है। आजादी से पूर्व आगरा, इटावा, भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर जनपदों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक छोटा सा राज्य था जिसे भदावर एस्टेट के रूप में जाना जाता था।

संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ

मोदी सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में आरक्षण को लेकर हाल में एक महत्वपूर्ण पहल की। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण का विस्तार किया जाएगा। यह भाजपा जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा उठाया गया चतुराई भरा कदम है। इसके माध्यम से उसने अपने मूल मतदाताओं को खुश रखते हुए तमाम क्षेत्रीय दलों के जातिगत समर्थन में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा चार जोड़ी गई। इसके अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रविधान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह राज्य द्वारा की गई आरंभिक स्वीकारोक्ति थी कि ऐसे नागरिकों के संरक्षण के लिए आरक्षण या ऐसी अन्य नीतियां आवश्यक थीं। ओबीसी को लेकर आजादी के बाद से ही सुगबुगाहट जारी रही है। इस मसले की पड़ताल के लिए कई आयोग और समितियां गठित की गईं। इनमें काका कालेलकर आयोग प्रमुख था। कालेलकर आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यों में भी दर्जनों आयोग सक्रिय रहे। सरकार ने कालेलकर आयोग की रपट पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसमें उसे गंभीर विरोधाभास महसूस हुए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स ने राज्य में ओबीसी को लेकर हैवनूर आयोग गठित कर उसकी रपट के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने राज्य में ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का एलान किया। वह ओबीसी के उप-वर्गीकरण के भी धुर समर्थक थे। इसके बाद मंडल आयोग की वजह से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर मुखरित हुआ। मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी सरकार ने किया था। आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। उसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पड़ताल और उनके सुधार के उपाय सुझाना था। मंडल आयोग ने आर्थिक पिछड़ेपन का संज्ञान नहीं लिया। आयोग की दृष्टि में देश की 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी के दायरे में आती है, लिहाजा उसके अनुसार सभी नौकरियों में उनका 52 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार बनता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर दी। ऐसे में आयोग ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटे की सिफारिश की। मंडल आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, लेकिन समता का सिद्धांत एक दोधारी तलवार है। यह जीवन की दौड़ में सशक्त और अशक्त को एक ही पायदान पर रखता है। चूंकि आयोग का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पड़ताल करना था, इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन को चिन्हित करना उसके एजेंडे में नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी समाज की मानवीयता के स्तर का निर्धारण इसी से होता है कि वह अपने कमजोर, अशक्त और साधनहीन सदस्यों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है। यद्यपि जाति अभी भी पिछड़ेपन को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक है, लेकिन समय के साथ उन गरीब वर्गों के स्वर भी मुखर हुए हैं, जो सामाजिक ढांचे में ओबीसी से ऊंचे स्तर पर माने जाते हैं।

रोजी-रोटी छीनने वाला अन्नदाता हरगिज नहीं हो सकता

किसान संगठन न केवल दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठे हैं, बल्कि उनके धरना-प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं के अलावा भी जारी हैं। उनके कारण भी लोगों को समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। संकट केवल यह नहीं कि लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यह भी है कि बहुत से लोगों की रोजी-रोटी के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ के उद्योगों के सामने तो कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाल की एक खबर के अनुसार बहादुरगढ़ के उद्योगों का कुल टर्नओवर करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। किसान आंदोलन की वजह से उन्हें अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बहादुरगढ़ के उद्यमियों की मानें तो दिल्ली को जोड़ने वाला टिकरी बार्डर बंद होने से इस क्षेत्र की फैक्ट्रियों के वाहनों को खेतों के कच्चे रास्ते से होकर दिल्ली जाना पड़ता है। इस रास्ते से एमसीडी को टोल देना पड़ता है और रास्ता देने के लिए खेतों के मालिकों को प्रति वाहन सौ-सौ रुपए भी। अब बारिश के कारण खेतों के रास्ते में पानी भर गया है और वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके किसान संगठन सड़क खाली करने को तैयार नहीं। बहादुरगढ़ चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुसार किसान संगठनों की रास्ताबंदी के कारण करीब सात लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है। इसके अलावा लोगों के लिए टिकरी बार्डर आना-जाना भी दूभर है। यही कहानी सिंघु बार्डर पर भी है। दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाली यहां की सड़क पर कब्जा होने की वजह से आसपास के लगभग 40 गांवों के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह उनकी भी नहीं सुनी जा रही, जो गाजीपुर बार्डर यानी यूपी गेट बाधित होने से आजिज आ चुके हैं। सड़कों को बाधित करना गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन क्षोभ और लज्जा की बात यह है कि न तो पुलिस के कान पर जूं रेंग रही है, न सरकार के और न ही उस सुप्रीम कोर्ट के, जिसने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। तथाकथित अन्नदाता किस तरह लोगों के पेट पर लात मारने का काम अन्यत्र भी कर रहे हैं, इसका एक और उदाहरण है लुधियाना में अदाणी समूह की ओर से अपने लाजिस्टिक पार्क को बंद किया जाना। इस पार्क का उद्देश्य पंजाब के उद्योगों को आयात और निर्यात के लिए रेल और सड़क मार्ग से कार्गो सेवा उपलब्ध कराना था। इस साल जनवरी में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने लाजिस्टिक पार्क के बाहर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। यह काम इस दुष्प्रचार की आड़ में किया गया कि कृषि कानूनों से तो असल फायदा अदाणी और अंबानी को होगा। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी के कारण लाजिस्टिक पार्क का काम ठप हो गया। कंपनी की तरफ से पंजाब सरकार को कई बार धरना हटाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उकसाने और बरगलाने वाली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में अदाणी समूह ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अमरिंदर सरकार को इस मामले का हल निकालने के आदेश दिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। थक-हारकर अदाणी समूह ने अपने इस पार्क को बंद करने का फैसला लिया। आखिर कोई कंपनी कब तक खाली बैठे लोगों को वेतन देती? लाजिस्टिक पार्क बंद करने के फैसले से चार सौ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई। इसे इस तरह समझें कि तथाकथित अन्नदाताओं के कारण सैकड़ों लोगों के पेट पर लात पड़ गई। जो दूसरों के पेट पर लात मारने का काम करे, वह कुछ भी हो सकता है, पर अन्नदाता हरगिज नहीं हो सकता। किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर सड़कों पर बैठे लोग आम किसान हैं। ये किसान नहीं, छुटभैये नेता, फुरसती लोग या फिर आदतन आंदोलनबाज हैं, जिन्हें किसानों का नेता बताया जा रहा है, वे भी वास्तव में किसान नेता नहीं, बल्कि किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने और नेतागीरी का शौक पालने वाले लोग हैं। शायद ही कोई किसान नेता ऐसा हो, जो सचमुच खेती-किसानी का काम करता हो। आखिर योगेंद्र यादव जैसे लोग किसान नेता कैसे हो सकते हैं? किसान नेता और उन्हें हवा दे रहे राजनीतिक दल कुछ भी दावा करें।

> कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान संगठन अपने लोगों के साथ सड़कों पर उतरे थे, तब उन्हें अन्नदाता कहकर संबोधित किया गया था-न केवल समर्थकों की ओर से, बल्कि सरकार की ओर से भी, लेकिन बीते आठ महीनों में किसान संगठनों ने आम नागरिकों के समक्ष जैसी समस्याएं खड़ी की हैं, उसे देखते हुए उन्हें मुसीबतदाता ही कहा जा सकता है।

फसलों के रखरखाव पर कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा में वैज्ञानिकों ने दिया सुझाव, बोले

बढ़ेगा फसल उत्पादन और देशी गाय बनाएंगी आत्मनिर्भर

अमित सोनी, रायसेन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, आत्मा परियोजना द्वारा हाल ही में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में किया गया। परिचर्चा में मुख्य रूप से सोयाबीन में गर्डल बीटल व तना मक्खी का प्रकोप, उड़द में पीला मोजेक, मक्का में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। वैज्ञानिक डॉ. स्वप्निल दुबे ने चर्चा के दौरान किसानों को बताया कि खरीफ मौसम में फसल विविधिकरण के अंतर्गत सोयाबीन, धान व अरहर के अलावा खरीफ मक्का, स्वीट कॉर्न, तिल, हल्दी व अदरक आदि फसलों के उत्पादन की बात कही गई। साथ ही सोयाबीन की नई किस्म एनआरसी-130, एनआरसी-138, एनआरसी-142, कम अवधि की धान पूसा-1692 व तुअर की पूसा अरहर-16 की जानकारी दी गई।

लाभ की खेती कोदौ

रायसेन जिले में धान की खेती के साथ-साथ कम लागत तकनीक में लघु धान्य फसल कोदौ का भी उत्पादन लिया जा सकता है। यह फसल कम उपजाऊ भूमि, हल्की भूमि, व कम वर्षा की स्थिति में भी 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, जिसका बाजार मूल्य 8-10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक मिलता है।

70 एकड़ में बोवनी

गौरतलब है कि सीरॉक संस्था, भोपाल के द्वारा औबेदुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम लुलका में कृषि विज्ञान केंद्र, रायसेन के तकनीकी मार्गदर्शन में लगभग 70 एकड़ में आदिवासी महिला कोदौ की उन्नत किस्म जेके-137 का उत्पादन शुरू किया है।

कीटनाशकों के उपयोग से बचें

कृषि वैज्ञानिक प्रदीप कुमार द्विवेदी द्वारा सोयाबीन, धान, अरहर फसल के प्रमुख कीट व रोग संबंधी जानकारी दी गई व सोयाबीन, मूंग, उड़द में पीला रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 600 मिली प्रति हेक्टेयर या एसीटामिप्रिड 20 एसपी 125 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की जानकारी दी गई। साथ ही शुरुआती अवस्था में रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करने व सिंथेटिक पाइराथ्राइडस कीटनाशकों का उपयोग न करने की सलाह दी गई।

गिर व साहीवाल गाय पालन से बढ़ेगा दूध का उत्पादन

वैज्ञानिक डॉ. मुकुल कुमार द्वारा बरसाती प्याज, मुनगा, फलदार पौधे आम, अमरूद, सीताफल व वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान गुप्ता द्वारा गाय की देशी किस्म गिर, साहीवाल व भैंस की मुर्रा व भदावरी नस्लों के साथ दुग्ध उत्पादन संबंधी जानकारी दी गई।

सूर्यवंशी ने किया संचालन

वैज्ञानिक रंजीत सिंह राघव द्वारा खरीफ फसलों में समन्वित पोषण प्रबंधन व वैज्ञानिक लक्ष्मी चक्रवर्ती द्वारा मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण व न्यूट्रीशनल किचिन गार्डन संबंधी तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन आलोक कुमार सूर्यवंशी द्वारा किया गया।

45 किसान हुए शामिल

इस कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में सांची, औबेदुल्लागंज, सिलवानी, गैरतगंज, उदयपुरा ब्लॉक के ग्राम गिरवर, वीरपुरा, देहगांव, धनियाखेड़ी, सियरमऊ, मगरधा, लुलका, सुलतानगंज के लगभग 45 किसानों ने भाग लिया।

यह भी रहे मौजूद

परिचर्चा में अनुविभागीय कृषि अधिकारी, जीएस रैकवार, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायसेन के वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख डॉ. स्वप्निल दुबे, वैज्ञानिक प्रदीप कुमार द्विवेदी, रंजीत सिंह राघव, डॉ. अंशुमान गुप्ता, और जिले में पदस्थ आत्मा योजनान्तर्गत बीटीएम सुरेश कुमार परमार, हीरालाल मालवीय, रघुवीर सिंह, योगेश शर्मा व सीरॉक संस्था के विजय शर्मा व राकेश शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे।

बंजर भूमि में हल्दी की खेती कर निकाला जाएगा तेल

पहली बार 160 महिलाओं ने हल्दी की खेती की अपनाई राह

यह है खास

- खेती करने बंजर भूमि को 10 हजार रुपए में बनाया उपजाऊ
- पांच क्विंटल 25 हजार रुपए में लाया गया बीज

संवाददाता, बालाघाट

जिले के ग्राम जमुनिया में पहली बार 16 आजीविका स्व सहायता समूह की 160 महिलाओं ने हल्दी की खेती करने संयुक्त राह अपनाई है। समूह की एक महिला सदस्य की डेढ़ एकड़ बंजर भूमि को खेती करने लायक बनाया गया। फिर वहां वायगांव हल्दी की खेती करना शुरू कर दिया। हल्दी लगाने से लेकर देखरेख का पूरा काम महिलाएं ही करती हैं। हल्दी इसलिए लगाई गई है कि इससे दोहरा लाभ मिलने वाला है। पहले हल्दी से तेल निकाला जाएगा। फिर बाजार में बेची जाएगी जिससे कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिल सकेगा। समूह की संगठन सचिव रंगीता तिलगकर ने बताया कि आजीविका मिशन कटंगी के अंतर्गत जमुनिया में दो वर्ष पूर्व स्व सहायता समूह का गठन हुआ। समूह अध्यक्ष पंचेश्वरी मर्सकोले की डेढ़ एकड़ जमीन सालों से बंजर थी। इसे खेती करने लायक बनाया गया और हल्दी से शुरुआत कर दी।

20 किलो में एक लीटर तेल

एक किलो हल्दी 80 से 90 रुपए और तेल 700 से 800 रुपए प्रति लीटर बिकता है। 20 किग्रा हल्दी से एक लीटर तेल निकलता है। तेल का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है और हल्दी खाने के काम में आती है। समूह अध्यक्ष पंचेश्वरी मर्सकोले, कोषाध्यक्ष शिशुला देवाहे, रंगीता तिलगकर समेत अन्य महिलाओं का खेती करने में सहयोग है।

महाराष्ट्र में बेंचेंगे

हल्दी की खेती मई से जून माह में होती है और छह माह में तैयार हो जाती है। बोनकट्टा के ग्राम हरदोली में निजी प्लांट में हल्दी की फसल निकलने पर वहां तेल निकाला जाएगा। इसके बाद हल्दी को महाराष्ट्र में बेच सकेंगे।

इनका कहना है

ग्राम जमुनिया में 16 स्व सहायता समूह हैं। 160 महिलाओं को हमारे अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी है। इसके बाद से संयुक्त रूप से महिलाएं हल्दी की खेती कर रही हैं। अच्छा लाभ मिलने पर आगामी साल रकबा बढ़ाया जाएगा।

■ **प्रतिमा सोनी**, ब्लॉक प्रबंधक, मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जपं कटंगी

किसानों की आय बढ़ाने आईआईटी दिल्ली और इफ्को मिलकर करेंगे काम

किसानों की आय दोगुनी करने में जुटा इफ्को

संवाददाता, भोपाल/दिल्ली

किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीर्ष उर्वरक सहकारी संस्था-इफ्को यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दावा किया जा रहा है किसानों की तरक्की के लिए यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। इस समझौते के जरिये दोनों ही संस्थान एक-दूसरे की प्रयोगशालाओं का प्रयोग करेंगे और किसानों की तरक्की के लिए काम करेंगे।

इफ्को 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अत्यधिक उन्नत कृषि तकनीकी परियोजनाओं को विकसित करने और देश में सटीक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी के तहत इफ्को का अनुसंधान और विकास इकाई, नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) और दिल्ली आईआईटी सहयोगात्मक परियोजनाओं के लिए मिल कर काम करेंगे। समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली और इफ्को एक-दूसरे की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल कर अनुसंधान परामर्श कर केंद्रित संयुक्त अनुसंधान पर जोर देंगे।

समस्याओं का खोजेंगे हल

बीते माह 20 जुलाई को हस्ताक्षरित यह समझौता ज्ञापन कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी विकास के दायरे को विस्तृत करेगा। यह भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। इफ्को के वैज्ञानिक-इंजीनियर और आईआईटी दिल्ली के अकादमिक अनुसंधान संकाय-विद्वान संयुक्त रूप से चुनौतीपूर्ण कृषि और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव समाधान खोजेंगे।

इनका कहना है

किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इफ्को हमेशा नई तकनीकों को अपनाने के लिए तत्पर रहता है। हम खेती की लागत को कम करने के स्थाई और अभिनव समाधान खोजने में विश्वास करते हैं। इसी के चलते किसानों की आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल विकसित किया है। हम स्थाई कृषि के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

डॉ. यूएस अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफ्को

मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहन आधुनिक कृषि प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो देश के किसानों के लिए फायदेमंद होगा। आईआईटी दिल्ली को इफ्को के साथ सहयोग करने और आपसी हित की भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने में खुशी हो रही है।

प्रो. वी रामगोपाल राव, निदेशक, आईआईटी दिल्ली

» अब प्रदेश से पॉलीथिन हटेगी, रूट ट्रेनर तकनीक बनेगी सहारा

» वन विभाग की 171 नर्सरी, हर साल छह करोड़ पौधे हो रहे तैयार

मध्य प्रदेश में छाएगी हरियाली

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश की हरियाली में पॉलीथिन के दाग मिटाने के लिए राज्य सरकार का वन विभाग रूट ट्रेनर (पौधे रोपने की विशेष ट्रे) का सहारा लेगी। अगले साल से विभाग की नर्सरियों में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले साल प्रयोग के तौर पर रूट ट्रेनर में पांच हजार पौधे ही तैयार किए जाएंगे। इसकी सफलता के बाद आगामी वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे पौधे तैयार करने और रोपण स्थल तक ले जाने में पॉलीथिन का इस्तेमाल कम हो जाएगा और जमीन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग की 171 नर्सरी हैं। इनमें हर साल करीब छह करोड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। इन्हें जुलाई माह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रोपा जाता है। इन पौधों को तैयार करने के लिए करीब आठ करोड़ पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल होता है। पौधे लगाते समय ये पॉलीथिन रिसाइकल करने के बजाय निकाल कर फेंक दी जाती हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। इसे लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो साल पहले पौधे तैयार करने में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, पर प्रदेश में इसका विकल्प नहीं तलाशा जा सका था।

ये होता है रूट ट्रेनर

यह उम्दा किस्म के प्लास्टिक से बनाई गई ट्रे होती है। इसमें गिलास जैसे कई ट्रेनर होते हैं। इनमें थोड़ी मिट्टी, खाद और बीज डालकर पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें छह से 10 इंच के पौधे भी रोपने लायक हो जाते हैं। ट्रे को पौधारोपण की जगह ले जाकर मिट्टी सहित पौधे को निकालकर रोपा जाता है।

15 साल काम आएंगे रूट ट्रेनर

अधिकारियों के मुताबिक रूट ट्रेनर का पर्यावरण को साफ रखने में तो योगदान रहेगा ही। इससे सरकार को बचत भी होगी। दरअसल, पॉलीथिन का एक बार इस्तेमाल होता है। लाखों पॉलीथिन तो ऐसी निकलती हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पर रूट ट्रेनर अच्छे प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। इन्हें 10 से 15 साल तक उपयोग किया जा सकता है। इनके उपयोग से करोड़ों की संख्या में पॉलीथिन बैग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मिल रहे संकेत

शोध का विषय बनी चिरोटा के पत्तों पर लगी विचित्र बिमारी

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट

बालाघाट जिले के कई स्थानों पर चिरौटा के पत्तों पर विचित्र बिमारी देखने को मिल रही है। जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बालाघाट जिले के विभिन्न स्थानों के अलावा बालघाट मुख्यालय में मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के सामने लगे चिरौटा के पत्तों में भी कालापन देखा गया है। इस बीमारी को लेकर शोधकर्ताओं के द्वारा शोध किया जा रहा है। केसियाटूरा(बॉटनीकल नेम) से भी जाना जाता है। अमूमन बारिश के दिनों से में यह खरपतवार के तौर पर प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है।

इस वर्ष कई स्थानों पर चिरौटा के पत्तों के ऊपरी और खासकर नीचे की ओर काले दाग देखने मिल रहे हैं। इस संबध में अन्नदाता किसान संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडला नैनपुर और कान्हा से लगे जिलों में इस तरह की बिमारी चिरौटा के पत्तों में देखा जा रहा है। जिसमें उनके द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने पर मंडला जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम की टीम के द्वारा इस बीमारी को लेकर शोध भी किया गया है। चिरौटा के पत्तों पर कालापन की इस बिमारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि इस तरह की बीमारी चिरौटा के पत्तों पर देखी जा रही है और यह जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संकेत भी हो सकते हैं।

भाजी के रूप से किया जाता है उपयोग

बालाघाट जिले के वन बाहुल्य क्षेत्र और यहां के ग्रामीण बारिश के दिनों में चिरौटा के पत्तों की सब्जी बनाकर खाते हैं। ऐसे में इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीणजनों को इस भाजी का सब्जी के रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। जब तक कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस विचित्र बीमारी को लेकर कोई परिणाम सामने नहीं आता है। मंडला जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के बाद जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के पौधकार्यिकी विभाग पौध रोग विभाग और कीट रोग विभाग भेजा गया है। ताकि इस विचित्र बीमारी की वास्तविकता सामने आ सके।

बीमारी के खोज में जुटे वैज्ञानिक

इस पौधे की ऊंचाई लगभग 6 इंज होती है। लोग इसकी भाजी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। वहीं इसकी फल्ली बीज का उपयोग चाय काफी बनाने और तेल औषधीयगुणों के लिए किया जाता है। जिसे खाज-खुजली और अन्य बीमारी में किया जाता है। इस संबध में मुख्य वन सरंक्षक बालाघाट और राणा हनुमान सिंह कृषि महाविद्यालय केंद्र बडगांव के वैज्ञानिक डॉ. आरएल राउत को दी गई है। वे अपने स्तर पर चिरौटा में इस विचित्र बीमारी को लेकर कार्य कर रहे हैं।

इनका कहना है

चिरौटा पर यह बीमारी पहली बार देखी जा रही है, जो कि कान्हा नेशनल पार्क से लगे बालाघाट, मंडला व नैनपुर इलाकों में देखी जा रही है। जिसको लेकर वैज्ञानिक सतर्क हैं। शोध का परिणाम आने तक इसकी भाजी का सेवन ग्रामीण न करें।

सारस्वत मुरलीमनोहर श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्यदाता किसान संगठन

चिरौटा पर विचित्र बीमारी संज्ञान में आई है। इस बिमारी को लेकर हम भी चिरौटा के पत्तों को देख रहे हैं। इसमें ब्लैक फंगस सा पत्तियों के पीछे दिखाई दे रहा है। इसका सेंपल वरिष्ठ कार्यालय में भेजा जाएगा।

आरएल राउत, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि केंद्र बडगांव

चिरौटा के पत्तों में कालेपन की विचित्र बीमारी का पता चला है। यह शोध का विषय है। शोध होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ग्रामीण इसके सेवन में सावधानी बरतें।

एनके सनोडिया, सीसीएफ, बालाघाट

वैज्ञानिक मौके पर पहुंचकर स्थिति का ले रहे जायजा

मंडला में फसल को नुकसान पहुंचा रहे शंख और घोंघे

जावेद अली, मंडला

विकासखंड मंडला के कुछ क्षेत्रों में शंख और घोंघे का प्रकोप खेतों में देखा जा रहा है। जिससे किसानों की फसल व सब्जी प्रभावित हो रही है। जिसकी जानकारी किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी को भी दी गई। जिसके बाद वैज्ञानिक दल मौके पर खेतों में पहुंचकर जायजा लिया है और उपचार भी इनसे निपटने किसानों को बताया गया है।

कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वरिष्ठ विज्ञानियों एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम को दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम सुकतरा विकासखंड मंडला के कृषकों के खेतों में शंख या स्नेल और घोंघे का प्रकोप व्यापक रूप में है। जिससे उनकी सब्जियों और फसलों में काफी क्षति हो रही है। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वरिष्ठ विज्ञानियों डॉ. विशाल मेश्राम द्वारा केंद्र में पदस्थ विज्ञानियों डॉ. आरपी अहिरवार, नीलकमल पंद्रे आत्मा परियोजना के उप परियोजना संचालक डॉ. आरके सिंह की संयुक्त टीम बनाकर राकेश सैनी एवं अन्य कृषकों के खेतों में निरीक्षण किया।

दिन में घोंघे निष्क्रिय

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि इन शंखों या स्नेल, घोंघो का रात्रि के समय अधिक आक्रमण होता है और इसी समय बेलवाली सब्जियों लौंकी, कद्दू, बरबटी एवं मक्का आदि सभी फसलों की पत्तियों को ये खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे फसलों की बढ़वार अवरुद्ध हो रही है। प्राय: सभी जानते हैं कि पौधे में पत्तियों के द्वारा ही भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। यदि पत्तियां ही नष्ट हो जाएगी। तो भोजन की कमी से पौधों की वृद्धि या बढ़वार रुकना स्वाभाविक है। ये शंख या स्नेल, घोंघे दिन के समय सुसुप्तावस्था में प्राय: निष्क्रिय पड़े रहते है।

पत्तियां इनका भोजन

डॉ. विशाल मेश्राम ने बताया कि घोंघा या शंख एक प्रकार के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के कड़े खोल होते हैं। इन जीवों को मोलस्क कहा जाता है। मोलस्क की 60,000 से अधिक किस्मों का अध्ययन अब तक किया जा चुका है। ये शंख मॉलस्क के शरीर के खोल होते है जैसे-जैसे मॉलस्क का आकार बढ़ता है वैसे ही वैसे यह खोल भी मजबूत और बड़ा होता जाता है ये जीव शाकाहारी होते हैं जो सभी प्रकार के पौधो जैसे घास, फसलों की पत्तियों का भोजन करते हैं।

नमक का घोल दिलाएगा छुटकारा

वैज्ञानिकों द्वारा इनके निदान के लिए दो प्रतिशत नमक का घोल या 3 मिली प्रति लीटर पानी की दर से बुझे हुए चूने के पानी का छिड़काव इनके उपर करने से इनकी रोकथाम की जा सकती है। या 15 प्रतिशत मेटाल्डीहाईड चूर्ण का 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर या 50 प्रतिशत मेटाल्डीहाईड पॉवडर के घोल का 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है।

श्री पद्धति से धान की खेती में मिलेगा ढाई गुना अधिक उत्पादन

संवाददाता, डिंडोरी

जिले के किसानों को परंपरागत धान की खेती के स्थान पर श्री पद्धति से बोवनी के लिए प्रेरित कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा जिले भर में 35 से 40 हजार हेक्टयर में श्री पद्धति से धान की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में श्री पद्धति से धान की बोवनी की बात भी कृषि विभाग द्वारा बताई जा रही है। बताया गया कि परंपरागत तरीके से धान की खेती के स्थान पर श्री पद्धति से खेती करने पर लगभग दो से ढाई गुना अधिक उत्पादन होगा। श्री पद्धति से खेती के लिए किसानों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इस पद्धति से खेती के लिए जिले के विकासखंड डिंडोरी, शहपुरा और बजाग क्षेत्र के किसानों द्वारा अधिक रुचि दिखाई जा रही है।

खेती के लिए लगता कम पानी

विभाग के जानकारों की मानें तो श्री पद्धति से धान की खेती करने में अधिक लाभ है। इस पद्धति से खेती करने में फसल में रोग भी लगने की संभावना भी कम रहती है। साथ ही पानी की आवश्यकता भी परंपरागत खेती की अपेक्षा कम होती है। उर्वरक और रासायनिक दवाओं कीटनाशक का कम प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में बारिश की स्थिति जिले में अच्छी न होने के चलते किसानों को श्री पद्धति से खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को खेती की तैयारी से लेकर पौधों की रोपाई की पूरी जानकारी दी जा रही है।

कम बीज में अधिक उत्पादन

श्री पद्धति से धान की खेती करने में लागत भी कम आती है। परंपरागत खेती में एक हेक्टेयर में जहां 50 से 60 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, वहीं श्री पद्धति से धान की खेती में बीज जरूरत महज पांच से छह किलो ही होती है। श्री पद्धति से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। परंपरागत खेती की अपेक्षा श्री पद्धति से खेती करने पर दो से ढाई गुना अधिक उत्पादन धान का होता है। ऐसे में किसानों को कम बीज में अधिक उत्पादन मिलेगा। जिले में इस वर्ष धान की खेती के लिए एक लाख 31 हजार हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से श्री पद्धति से खेती का लक्ष्य 35 से 40 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।

इनका कहना है

परंपरागत धान की खेती के स्थान पर जिले के किसानों को श्री पद्धति से धान की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस वर्ष जिले में श्री पद्धति से धान की बोवनी का लक्ष्य 35 से 40 हजार हेक्टेयर में रखा गया है। वर्तमान स्थिति में लगभग 25 हजार हेक्टेयर में श्री पद्धति से धान की बोवनी भी हो चुकी है। श्री पद्धति में कम बीज, कम पानी में अधिक उत्पादन मिलता है। किसानों को खेती की पूरी जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है जिससे वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

-**अश्विनी झारिया,** उपसंचालक कृषि डिंडोरी

पंडितजी! 26 साल से रोप रहे घर-मंदिरों में पारिजात का पौधा

जागरुकता की मिशालः चल रहा सिलसिल आज भी जारी

संवाददाता, कटंगी

कटंगी तहसील मुख्यालय के वार्ड 14 में रहने वाले पंडित महेश शर्मा द्वारा औषधीनुमा पारिजात के पौधे जागरूक लोगों के तक और गांव-गांव के मंदिर परिसर में लगवाने का बीड़ा उठाया है। पौधारोपण करने का सिलसिला अनवरत चला आ रहा है। इसकी शुरुआत महेश शर्मा ने पंढरपुर से पारिजात के पौधे लाकर की थी। दरअसल, 26 वर्षों में 155 मंदिर और एक सैकड़ा गांवों के 2980 मकानों के आंगन परिसर में पौधे लगाने का कार्य किए है। उनका लक्ष्य पारिजात का पौधा हर मंदिर परिसर में लगा रहने का है। पंडित महेश शर्मा ने बताते हैं कि 26 वर्षों पूर्व महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर में भगवान विठ्ठल रूखमाईं के दर्शन करने गए थे। वहां पर मंदिर परिसर के समीप जिस धर्मशाला में रात में रुके थे। सुबह मंदिर के पुजारी से उनकी भेंट हुई। जिसने उन्हें धर्मशाला के सामने लगे पारिजात के पेड़ के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने कहा कि पहले पेड़ को देखकर आओ फिर उसके संबंध में जानकारी देते हैं। पुजारी ने पारिजात के बारे विस्तार से समझाया। जिसके बाद पंढरपुर और उसके आसपास प्रयास करके 10 पारिजात के पौधे कटंगी नगर अपने साथ लेकर आए थे।

अब पौधे हो गए पेड़

पारिजात पेड़ के अद्भुतगुणों के बारे में जानने के बाद अपने निजी वाहन सूमो से नागपुर गए और वहां के सभी नर्सरी से ढूंढकर पारिजात के 100 पौधे कटंगी नगर लेकर आए और मंदिर परिसर व जागरूक लोगों के यहां पर रोपित करने के बाद महत्व बताते गए। जिसका नतीजा यह है कि सौ से अधिक गांवों के मंदिर व घर आंगन में पारिजात के पौधे लगे हुए हैं। जो अब पेड़ में तब्दील होते जा रहे हैं।

औषधीयनुमा पारिजातः पर्यावरण को बचाने के साथ ही औषधीयनुमा पारिजात पौधा को गांवों के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए बचपन से मन में ठान रखी थी। पारिजात के पौधे को जिस स्थान में लगा दिया जाए उस जगह पौधा पेड़ में तब्दील होने के बाद बेहतर वातावरण, पानी की प्रचुर मात्रा बनी रहती है। पारिजात गुणकारक होने के साथ ही जोड़ों का दर्द, साइटिका समेत अन्य बीमारी के लिए रामबाण साबित है। पौधे लगाने की शुरुआत सबसे पहले शहर के मंदिरों से की थी। उसके बाद गांव-गांव जाकर मंदिर परिसर में एक-एक पौधा रोपित करते गए और ग्राम में ऐसे व्यक्ति जो पेड़ बचाने सक्षम होते हैं, उन लोगों के आंगन में पौधा लगाकर देखभाल करने का जिम्मा सौंपते है।

इतने गांवों में लगाए पौधेः पारिजात के पौधे नगर के श्रीकृष्ण मंदिर परिसर, शिव मंदिर, श्रीराम मंदिर, हनुमान मंदिर के अलावा ग्राम जाम, सिंगोड़ी, बनेरा, कटेधरा, नांदी, चिकमारा, उमरी समेत 100 गांवों के मंदिर परिसर और जागरूक लोगों के घरों के आंगन में यह पौधा निःशुल्क लगाए हैं। ये पौधे अधिकांश जगह पेड़ में तब्दील होने से हरे भरे दिखाई देते हैं। पारिजात के पौधे कभी जबलपुर या फिर नागपुर की नर्सरी से बुलवाते हैं। इस वर्ष 1000 पौधे बुलवाए हैं। पारिजात का एक पौधा 80 से 90 रुपए में मिलता है। 26 वर्षों में साढ़े पांच लाख रुपए पौधे लगाने में खर्च कर दिए है।

अन्न उत्सव

राशन पाकर खुश हुई हल्की बाई

अशोकनगर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के फोटो वाले बैग में राशन पाकर हल्की बाई ओझा ऊर्जा कालोनी अशोकनगर काफी खुश हुई। खुशी का इजहार करते हुए हल्की बाई ने कहा कि देश के प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने संकटकाल में भी राशन उपलब्ध कराकर हम गरीबों को जो मान सम्मान दिया है, वह काफी है।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवाड़ी के चंद्रभान से किए 12 सवाल और जाने हाल

चंद्रभान जी...मैं 2 हजार भेजता हूं, मिलते हैं या नहीं, हां सर! मिल रहा है...

संवाददाता, भोपाल/ टीकमगढ़

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव कार्यक्रम जिले में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। निवाड़ी जिले मड़िया गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां से हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाइव बात भी की। मप्र के चार हितग्राहियों से प्रधानमंत्री को बात करनी थी, लाइव कनेक्शन कनेक्ट न हो पाने के कारण प्रधानमंत्री ने बुरहानपुर के हितग्राही से सबसे पहले बात की। इसके बाद सबसे बाद में निवाड़ी जिले के हितग्राही से सुबह 11.28 बजे बात हो सकी। निवाड़ी जिले से दो हितग्राहियों में चंद्रभान विश्वकर्मा और माया धुर्वे की बात पीएम से होना दर्शाया गया था, सिर्फ मडिया गांव निवासी 62 वर्षीय चंद्रभान विश्वकर्मा से ही बात हो सकी। सबसे बाद में चंद्रभान से बात कर उनकी आजीविका सहित भरण पोषण और परिवार को लेकर जानकारियां

पीएम ने ली। साथ ही उनके कार्यों की उन्होंने सराहना भी की। पीएम से बात करने वाले हितग्राही चंद्रभान ने कहा कि पीएम से बात करके बेहद अच्छा लगा। उन्हें पहले ही जब पीएम से बात करने के लिए बताया गया था। तब से ही वह बेहद खुश हैं। मड़िया गांव के चंद्रभान ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बनकर कार्य करने की सलाह मैं देता हूं। मैं ही अपने रोजगार को स्थापित कर आगे बढ़ रहा हूं। चंद्रभान विश्वकर्मा से पीएम ने उनके व्यवसाय के बारे में पूछा। चंद्रभान ने बताया कि खटिया व अन्य किसानी सामान बनाते हैं। आधा हेक्टेयर जमीन है, उस पर गेहूं-मूंग उगाते हैं। परिवार के चार सदस्यों का भरण-पोषण करते हैं। इसके बाद पीएम ने पूछा कि मैं जो 2 हजार रुपए भेजता हूं, वो आपको मिलते हैं या नहीं। पीएम आवास योजना का लाभ मिला है? इस पर चंद्रभान ने हां में जवाब दिया।

प्रधानमंत्री और चंद्रभान की बातचीत के अंश

पीएम: नमस्कार चंद्रभान जी..
चंद्रभान: नमस्ते सर जी..
पीएम: क्या करते हैं आप..
चंद्रभान: सर मैं बढ़ई का काम करता हूं।
पीएम: इस कार्य के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या घर में पहले से कार्य होता है।
चंद्रभान: सर घर परिवार में पहले से होता चला आ रहा है।
पीएम: इसमें विशेष क्या बनाते हो..
चंद्रभान: सर खटिया बगैरा विशेष है, जिसका कार्य क्षेत्र में ठीक चलता है।
पीएम: जमीन कितनी है आपकी।
चंद्रभान: सर मेरी आधा हेक्टेयर जमीन है।
पीएम: क्या-क्या इस जमीन में उगाते हो।
चंद्रभान: सर मौसम के हिसाब से फसलों को उगाते हैं।
पीएम: राशन ठीक से मिल रहा है।
चंद्रभान: सर राशन मिलने की व्यवस्था बेहद ठीक है, जो हर माह प्राप्त हो रहा है।
पीएम: राशन मिलता है अच्छी बात है, आपको क्या भारत सरकार की पीएस आवास योजना का लाभ मिला है।
चंद्रभान: जी सर, मुझे दो साल पहले ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
पीएम: घर अच्छा बना है।
चंद्रभान: हां सर।
पीएम: सपनों का घर बना।
चंद्रभान: हां सर।
पीएम: मेहमान आते हैं।
चंद्रभान: हां सर, मेहमान भी आते हैं, उसी घर में रूकते हैं।
पीएम: बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं।
चंद्रभान: सर, एक बच्चा 10वीं और दूसरा 12वीं कक्षा में पढ़ता है।
पीएम: चलिए अच्छा है, आपको राशन और घर सब मिलता है। आप पीओएस मशीन के बारे में भी जानते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।

गांव बनाएं आत्मनिर्भर

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रायसेन जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हितग्राहियों को राशन वितरित किया। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है कि वे अपनी बसाहट के सभी पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा दिलाएं, जिससे गांव तथा गांव वाले आत्म निर्भर बन सकें।

-अब हजारों पौध तैयार, माली को मिला काम

सात साल बाद वीरान नर्सरी में दिखी हरियाली

अवधेश दंडोतिया, मुरैना

पोरसा कस्बे की एक अदद नर्सरी, जो सात सालों तक वीरान पड़ी रही, लेकिन अब यही नर्सरी हजारों पौध तैयार कर रही है, जो हरियाली लाने में कारगर साबित होगी। कस्बे में सेंथरा अहीर पंचायत में मौजूद इस नर्सरी को महज कुछ मामूली कमियों के चलते सात सालों तक बंद रखा गया था। जिसके बाद लगभग तीन साल पहले इसे फिर से चालू करने की सुध ली गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि अब यह नर्सरी पौध तैयार कर रही है। गौरतलब है कि पचपेड़ा के पास उद्यानिकी विभाग की नर्सरी मौजूद है। कई बीघा में फैली यह नर्सरी तीन साल पहले तक पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई थी। इसकी वजह थी कि यहां पानी का इंतजाम नहीं था। महज पानी के अभाव में इस नर्सरी को वीरान ही छोड़ दिया गया।

40 हजार पौध तैयार

खासबात यह है कि यहां माली से लेकर अन्य सभी कर्मचारियों की नियुक्ति थी, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था। नर्सरी सूनी पड़ी हुई थी। इसके बाद जैसे तैसे यहां एक पानी का बोर कराया गया। जिसके बाद इस नर्सरी पर यहां के कर्मचारियों ने काम शुरू किया। जिसका परिणाम यह हुआ है कि अब इस नर्सरी में 40 हजार पौध तैयार की जा चुकी है, वहीं 20 हजार पौध ऐसी हैं जो तैयार होने वाली है।

नर्सरी में हरियाली

अभी तक हरियाली महोत्सव के लिए बाहर से ही पौध मंगानी पड़ती थी। जिसमें लाखों रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब पोरसा कस्बे की यह नर्सरी पूरी तरह से हरीभरी हो चुकी है और हजारों पौध तैयार की जा चुकी है, जो हरियाली महोत्सव के लिए बेहद कारगर साबित होगी।

दिन-रात जुटे अधिकारी

इस नर्सरी की देखभाल अधीक्षक अमर सिंह जाटव कर रहे हैं। इसके साथ ही रमेश सिंह माहौर, गंगा सिंह पटेल, मुन्ना सिंह कुशवाह, जीवाराम सखबार, महिपत सिंह सहित अन्य कर्मचारी यहां दिन रात पौध तैयार कर रहे हैं।

कस्बा होगा हरा-भरा

नर्सरी में इस समय अमरूद, नींबू, करोदा, सीताफल, जामुन, कटहल, गुल मोहर, कचनार, कदम, आमला, मेहंदी, सहजना, चांदनी, अनार, चम्पा, कनेर, गुड़हल, गुलाब, शहतूत पौध तैयार की जा रही है। यह तैयार पौधे जब लोगों के द्वारा जगह-जगह पर लगाए जाएंगे। उसके बाद जिससे कस्बे को हरा भरा बनाने में सहयोग करेगी।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लौरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिंण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)